भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 169

शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

लचीली जीवीसी का निर्माण

***169. श्री बी॰पार्थसारधी रेड्डी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के निर्माण के लिए एक सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और बाजार तक पहुँच, , व्यापार के सरलीकरण और वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 04.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 169 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : लोचपूर्ण वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) के लिए मजबूत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, उत्पादन में निवेश, व्यापार सहायता उपाय, घरेलू और वैश्विक उत्पादन नेटवर्कों के बेहतर एकीकरण के लिए अधिक बाजार पहुंच आदि अपेक्षित हैं।

इस संबंध में, भारत सरकार ने अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का निर्माण करने, विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

मल्टीमॉडल अवसंरचना प्लानिंग के लिए 'समग्र सरकार दृष्टिकोण' के साथ 13 अक्टूबर, 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरुआत की गई थी। पीएम गतिशक्ति जीआईएस-समर्थित प्लेटफॉर्म है, जो सड़क, रेलवे लाइन, बंदरगाह, अंतर्देशीय जलमार्ग, टेलीकॉम लाइन, पावर लाइन आदि की अवसंरचना के डाटा लेयर्स को सिंगल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है तथा मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक प्लानिंग को संभव बनाता है। विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएमपी का अत्यधिक उपयोग देखा गया है। देश में महत्वपूर्ण एक्जिम गेटवे से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए, 100 चिह्नित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 75,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

पीएम गतिशक्ति एनएमपी में सहायता के लिए, व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (सीएलएपी) के जरिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाकर सेवाओं में कुशलता लाने के लिए 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) शुरू की गई थी, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना, मानव संसाधनों का विकास, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक (एलडीपी) जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाना शामिल है। यूलिप, मंत्रालयों की 33 लॉजिस्टिक्स संबंधी डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत करता है, जबकि एलडीबी का संचालन एक्जिम कंटेनरों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, देश में निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुधार किए गए हैं जिसमें अन्य व्यावसायिक सुधारों के साथ-साथ उदारीकृत एफडीआई नीति, 14 प्रमुख क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर फोकस करने वाली विदेश व्यापार नीति 2023, अनुपालन बोझ को कम करने के उपाय, मेक इन इंडिया, एक जिला एक उत्पाद पहल, निर्यात हब के रूप में जिला पहल भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), प्राथमिकता के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र तक आपूर्तियां और बाजार पहुंच सुनिश्चित कर रहा है।

समग्र अवसंरचना प्लानिंग में सहायता करने तथा देश में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए भारतमाला और सागरमाला, निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस),

औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा औद्योगिक कॉरिडोर का विकास आदि कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

*****